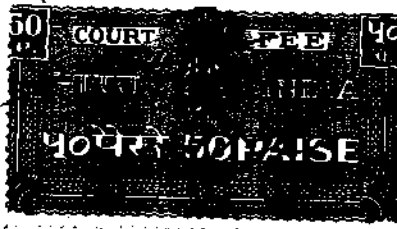
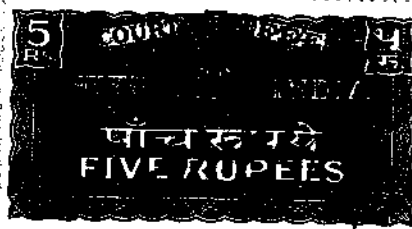


न्यायालय श्री मान अफ्जल महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालिबर;



मुसो कोसिल्या बाई धर्माली राम लाल निवासी ग्राम धमौर तहो
बान्धव मट विला गहडोल

C.F. 7.90

व नाम

मो प्रो शास्त्र

..... .. रत्या

अील विल आडा श्री अर कमिनर सीया
तंभाम दिनिक 20.3.94 बावत प्रकरण क्रमांक
358/93-94 .

2/10-3/2/538/94

R.P. 642

117-94
आजीव कोक्टर, विला
दिनांक 5 JUL 1994
का नाम

577194

मानववर,

अील के आधार निम्न है :-

- 1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आडा विधि एवं प्रक्रिया के विरती है।
- 2:- यह कि अील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के तम धारा 5, 14 परिली अधिनियम के तहत आयेदन कर अर कोक्टर के न्यायालय में ह्ये तदुभावना पूर्ण विल को भाक विले जाने बावत तहोपता बाही गई थी, व अर कोक्टर के न्यायालय में निगरानी अंदर म्याद प्रस्तुत कर दी गई थी, इतलिये अर कोक्टर के यहां प्रस्तुत निगरानी यदि अंदर म्याद थी, तो एक- एक दिन का त्यकटी करण देना कानून आवश्यक नही था, और अर कोक्टर के आदेश के बाद अील द्वारा एक- एक दिन का त्यकटी करण दिया गया है, परन्तु समानी कतत उपधारणा कर अधीनस्थ न्यायालय ने कृत की है।
- 3:- यह कि विलम धमा हेत अील ने धारा 5, 14 के

162.94
कोटर द्वारा काय विलम
एक कोटर
कोटर द्वारा काय विलम

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क० निग० 538/94

जिला ~~राज~~ शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पदाधिकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-7-2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० वाजपेयी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 358/93-94 में पारित आदेश दिनांक 30.3.94 के विरुद्ध इस न्यायालय में म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2-प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम घगोखर की शासकीय आराजी ख० न० 644/1 रकवा 0.405 है० में देवालय एवं मेला ग्राउन्ड अंकित है। उसी भूमि से संलग्न ख० न० 642/1 रकवा 1.603, 643 रकवा 0.21 646 रकवा 0.380 है०। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में लिखा है कि जिसकी आवश्यकता मेला के लिय भविष्य में पड़ सकती है। इसी भूमि की शिकायत भी नायब तहसीलदार को प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि जनता के निस्तार हेतु सुरक्षित खसरा खाना 12 में अंकित किये जाने के आदेश दिये थे। साथ ही उक्त खसरा नमबरान के अति कामकों के विरुद्ध धारा 248 के तहत तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अवधि के बाहर होने के कारण निरस्त की गई। इससे दुखी होकर आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर जिला शहडोल के न्यायालय में स्व० निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.1.94 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित बताते हुये निगरानी निरस्त की गई। इससे दुखी होकर आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहाँ</p>	

निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में दिनांक 30.3.94 के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक अवधि का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वरन् तथ्य को छुपाया गया है। अपील कालसीमा बाह्य होकर खारिज की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदिका द्वारा धारा 5, 14 परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन कर अपर कलेक्टर के न्यायालय में हुये सद्भावना पूर्ण विलंब को माफ किये जाने बावत सहायता चाही गई थी। उनके द्वारा अपर कलेक्टर के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और अपर कलेक्टर के आदेश के बाद अपीलार्थी द्वारा एक-एक दिन का स्पष्टीकरण दिया गया है परंतु मनमानी गलत उपधारणा कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

4-अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है कि जो उनके द्वारा अपील में उल्लेख किया गया है, उनका मुख्य रूप से अवधि विधाना धारा-5 परिसीमा अधिनियम 1963 के आवेदन पर जो दिया गया है कि अपर कलेक्टर के यहा समय सीमा में ही स्व0 निगरानी प्रस्तुत की गई थी।

5- मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों का अवलोकन किया। नायब तहसीलदार मानपुर के आदेश दिनांक 21.8.91 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयावधि बाह्य होने के कारण खारिज किया गया है। समय अवधि के अंतर्गत अपील न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने का प्रावधान है।

अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश प्रथम अपीलीय न्यायालय है संहिता की धारा-46 टिप्पणी "इ" में प्रावधान दिया गया है कि " जब अपील या पुनर्विलोकन कालसीमा की बाधा के कारण निरस्त होगा । ऐसा आदेश प्रथम या द्वितीय अपील में दिया गया है तब वह धारा 44 (2) के अंतर्गत अपील योग्य होगा। ऐसी ही व्यवस्था संहिता की धारा 47 की टिप्पणी "उ" में स्पष्ट रूप से दी गई है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः वैसे भी तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है। अतः निगरानी में मान्य करते हुये आदेश पारित किया जा रहा है। अतः निगरानी/अमील निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य